Student's Copy

2023

CONSTITUTIONAL AND ADMINISTRATIVE LAW OF INDIA

भारत की सांविधानिक एवं प्रशासनिक विधि

Time Allowed : 3 Hours] [*Maximum Marks* : 150

समय : 3 घण्टे पूर्णांक : 150

Marks are indicated against each question

प्रत्येक प्रश्न के अंक अंत में दिए गए हैं

Answer **six** questions, selecting **three** from each Group

प्रत्येक खण्ड से **तीन** प्रश्नों का चयन कर कुल **छः** प्रश्नों के उत्तर दें

Group—A

खण्ड—क

1. The Supreme Court of India in Kesavananda Bharati case affirmed that "the power of the Parliament to amend the Constitution is very wide but not unlimited". Critically analyse this statement with the help of decided cases. 25

भारत के उच्चतम न्यायालय ने केशवानन्द भारती के वाद में संस्थापित किया कि "संसद के पास संविधान संशोधन की सभी शक्तियाँ हैं परन्तु ये अमर्यादित नहीं हैं"। न्यायालयों के निर्णयों की सहायता से इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

2. *(a)* "The Directive Principles of State Policy which have been declared to be 'fundamental' in the governance of the country cannot be isolated from Fundamental Rights." Analyse critically. 12½

"राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों को, जिनको देश के शासन में 'मूल' घोषित किया गया है, मूल अधिकारों से विलग नहीं किया जा सकता है।" आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

(b) Has judiciary been a hindrance or facilitator in the interpretation of the Directive Principles of State Policy? Examine in the light of various judgements of the Supreme Court. 12½

क्या न्यायपालिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों की विवेचना में अवरोध या सहायक रही है? उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के प्रकाश में परीक्षण कीजिए।

3. Write short notes on the following : 12½×2=25

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(a) 'Doctrine of pleasure' along with its exceptions

'प्रसाद का सिद्धान्त', अपवाद सहित

(b) Doctrine of eclipse

आच्छादन का सिद्धान्त

4. *(a)* What is the true import of the phrase 'to be a witness' used in Article 20(3) of the Constitution of India? 12½

भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) में उल्लिखित शब्दसमूह 'साक्षी होना' का सही अर्थ क्या है?

(b) Whether a subpoena to access the Facebook page of the accused containing incriminating material would be hit by the right of accused against self-incrimination? 12½

क्या अभियुक्त के अपराध में फँसाने वाली सामग्रीयुक्त फेसबुक पेज के लिए पहुँच प्राप्त करने हेतु सपीना (subpoena) को अभियुक्त का आत्म-अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार प्रभावित करेगा?

5. "The Supreme Court of India has been consistent in expanding the horizon and scope of right to life and liberty, barring few exceptions." Analyse this statement in the light of the Supreme Court judgements. 25

''भारत का उच्चतम न्यायालय जीवन जीने और स्वतंत्रता के अधिकार का दायरा और व्याप्ति बढ़ाने के मामले में निरन्तर सक्रिय रहा है, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़कर।'' उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आलोक में इस कथन का विश्लेषण कीजिए।

Group—B
खण्ड—ख

6. "Power in the hands of administrative authorities is in the nature of public trust, and therefore, must be exercised in the best interest of the people." In this context, discuss the doctrine of public accountability. 25

''प्रशासनिक प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियाँ लोकन्यास के रूप में हैं, और इसलिए इनका उपयोग जनता के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।'' इस कथन को दृष्टिगत रखते हुए लोक दायित्वाधीन के सिद्धान्त को समझाइए।

7. What are the grounds on which the vires of a subordinate legislation can be challenged? Explain with the help of leading judgements. 25

किन आधारों पर अधीनस्थ विधायन की सीमाओं को चुनौती दी जा सकती है? महत्त्वपूर्ण निर्णयों की मदद से व्याख्या कीजिए।

8. "The purpose of the office of 'Lokpal' is not to adjudicate, but to provide regular machinery for investigating grievances against the administration in a discrete and informal manner." Critically examine this statement by providing proper justification of the office of the 'Lokpal' in India. 25

'' 'लोकपाल' के पद का उद्देश्य न्याय-निर्णयन करना नहीं है, अपितु प्रशासन के विरुद्ध शिकायतों के एक अलग और अनौपचारिक तरीके से अन्वेषण के लिए नियमित व्यवस्था प्रदान करना है।'' भारत में 'लोकपाल' के पद के उचित औचित्य के प्रतिपादन के साथ इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

9. "The law has been rightly laid down by the Supreme Court in the 'Vidyawati case'. Unfortunately within very short time a clear departure was made in the 'Kasturilal case' and the efficacy of the law laid down in the 'Vidyawati case' was considerably watered down by the Supreme Court." Discuss. 25

"उच्चतम न्यायालय के द्वारा 'विद्यावती के मामले' में विधि का उचित रूप से प्रतिपादन किया गया। दुर्भाग्यवश अति कम समय के अन्दर 'कस्तूरीलाल के मामले' में एक स्पष्ट प्रस्थान किया गया और उच्चतम न्यायालय के द्वारा 'विद्यावती मामले' में प्रतिपादित विधि की प्रभावकारिता काफी हद तक जलमग्न कर दी गई।" विवेचना कीजिए।

10. Write short notes on the following : 12½×2=25

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(a) Public interest litigation
जनहित याचिका

(b) Legitimate expectation
विधिसम्मत प्रत्याशा

★★★

SEAL